© 2017 IJSRST | Volume 3 | Issue 8 | Print ISSN: 2395-6011 | Online ISSN: 2395-602X
Themed Section: Science and Technology

प्राथमिक शिक्षा की समस्याएँ

श्रीमती किरन सिंह
सहायक आचार्य, शिक्षक शिक्षा संकाय, नेहरू ग्राम
भारती वि॰ वि॰ जमुनीपुर, कोटवा दुबावल,
इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत।

ABSTRACT

प्राथमिक शिक्षा जीवन में वही महत्व है जो दृढ़ एवं स्थायी भवन के निर्माण में उसकी आधारशिला का। शिक्षा मनुष्य को मानवता सिखाने वाला प्रथम सोपान हैं। शिक्षा के विभिन्न स्तरों प्राथमिक, माध्यमिक, तथा उच्च शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा ही समस्त शिक्षा की आधारशिला है। किसी भी राष्ट्र के विकास के जितना महत्व प्राथमिक शिक्षा का है उतना माध्यमिक या उच्च शिक्षा का नहीं है। राष्ट्रीय विचार धारा एवं चरित्र का निर्माण करने में इसका जितना महत्वपूर्ण स्थान है। उतना किसी दूसरी सामाजिक, राजनीतिक या शैक्षणिक गतिविधि का नही है।

इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि सब व्यक्तियों की शिक्षा या जन साधारण की शिक्षा ही राष्ट्रीय प्रगति का मूलाधार है। प्राचीन काल में प्राथमिक शिक्षा का दायित्व परिवार या घर को प्राप्त था। बालक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ही गुरूकुलों मे प्रवेश लेता था चूंकि उस काल में प्राथमिक शिक्षा की बागडोर ब्राम्हणों के हाथ में नही थी इसलिए उसकी घोर अवहेलना हुई परिणाम स्वरूपं देश का पतन हुआ। अत: इसका उत्थान करके ही देश का कल्याण हो सकता है

उन्नति की दौड़ में तथा आज के राष्ट्रीय परिक्षेप्य में प्राथमिक शिक्षा ही राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की आधारशिला है। वर्तमान तथा भविष्य के निर्माण का अनुपम साधन प्राथमिक शिक्षा ही है। कुल मिलाकर प्राथमिक शिक्षा हमारे संविधान द्वारा प्रतिष्ठित समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हैं।

प्राथमिक शिक्षा का महत्व इस बात से और भी बढ़ जाता है कि अधिकतर नागरिकों के लिए सम्पूर्ण शिक्षा इसी स्तर पर समाप्त हो जाती है अत: इस नींव को ससक्त बनाना बहुत आवश्यक है। इस सन्दर्भ में स्वामी विवेकानन्द का विचार था कि–"मेरे विचार से जनसाधारण की अवहेलना महान राष्ट्र पाप हैं और हमारे पतन के कारणें में से एक है। सब राजनीति
उस समय तक विफल रहेगी जब तक कि भारत में जन साधारण को एक बार फिर भली प्रकार शिक्षित नहीं कर लिया जायेगा। "

सन् 1898 ई 0 में तत्कालीन बडौदा नरेश ने यह घोषणा की कि उनके राज्य मे अमरेली नगर के एक क्षेत्र के 9 गांवों में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होगी। उन्हीं के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1906 में 2 गांवों में अनिवार्य शिक्षा की

व्यवस्था थी। इसी वर्ष नियम बनाकर सारे राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गयी। बड़ौदा नरेश के प्रयासों से प्रभावित होकर गोपाल कृष्ण गोखले ने भी तत्कालीन सरकार से प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता की माँग की। प्रारम्भ में उन्हें असफलता मिली किन्तु उन्हीं के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1917 में ब्रिटिश प्रशासन को भली यह महसूस हुआ कि स्वशासन संस्था ओं को चलाने के लिए जनता का शिक्षित होना आवश्यक है। अत: प्रान्तीय सराकरों ने इस दिशा मे कुछ कार्य किये। इस प्रकार बम्बई, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब में प्राथमिक शिक्षा की प्रगति 1930 तक निरन्तर होती रही। किन्तु 1931 से 1937 तक इसके विकास में अवरोघ उत्पन्न हो गया। इसके दो मुख्य कारण थे –

1. विश्व व्यापी आर्थिक अवसाद तथा दूसरा 1927 में हर्टाग समिति की नियुक्ति तथा प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का प्रस्ताव। फलस्वरूप स्वतन्त्रता प्राप्ति तक देश में बालकों के लिए 229 नगरों व 10,017 ग्रामों में तथा बालिकाओं के लिए दस नगरों में व 1,404 ग्रामों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था हो चुकी थी। 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान की धारा 45 में यह घोषणा की गई थ्ज्ञी कि दस वर्ष के अन्दर 6 से 14 वर्ष तक के समस्त बालक–बालिकाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा नि:शुल्क एवं अनिवार्य कर दी जायेगी। भारतीय शिक्षा आयोग ने भारत के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए शिक्षा को एक महत्वपूर्ण अंग माना है। शिक्षा की गुणवत्ता को जो ऊंचाई प्राप्त करनी चाहिये थी वह नही प्राप्त कर रहा है। सर्वेक्षण के आधार पर यह देखा गया है कि आज शिक्षित समाज का अशिक्षित समाज पर दबदबा बना हुआ है। शिक्षा की खराब व्यवस्था व्यवस्थित जीवन–यापन के तरीके को भी प्रभावित कर रही है। यह छात्र के साथ–साथ समाज व राष्ट्र के लिए भी दुखद है। आज किसी को यह ख्याल नहीं है कि प्राथमिक शिक्षा विश्वविद्यालयी और तकनीकी शिक्षा की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं।

इसकी अवहेलना के कारण ही बच्चे छोटे उम्र में ही हीनता का शिकार होते जा रहे हैं। ध्यान रखना होगा कि प्रारम्भिक शिक्षा उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा से अधिक जरूरी व महत्वपूर्ण है। तकनीकी शिक्षा में प्रति छात्र जितनी राशि आवंटित की जाती है गैर तकनीकी शिक्षा या विश्वविद्यालयी शिक्षा पर इसके आधे से भी कम खर्च होती है। प्राथमिक शिक्षा पर तो सरकारी खर्च नाममात्र का है। इस वजह से भी प्राथमिक शिक्षा की गुण्वत्ता में गिरावट आई है। अनिवार्य होने के साथ क्या साधन की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। सरकारों को यह कौन बतायें कि प्राथमिक शिक्षा पर व्यय होने वाला धन न्यूनतम है। पहले सभी स्कूलों में खेल के मैदान होते थे अब धीरे–धीरे सब व्यवस्था छिन्न–भिन्न होती जा रही है। विज्ञापनों में तो विभिन्न साधन बताये जाते हैं और उनका शुल्क भी लिया जाता है लेकिन व्यवस्था उपलब्ध नही करायी जाती। पाठ्यक्रम में भी समानता नही है आज प्राथमिक विद्यालयों का यदि सर्वांगीय अवलोकन करें तो हम पाते हैं कि प्राथमिक विद्यालय बच्चों और अभिभावकों को प्रोत्साहित करने का माध्यम न होकर हतोत्साहित करने का केन्द्र हो गया है।

पब्लिक स्कूल दूसरी प्रकार की हीनता का माध्यम बन रहे हैं केवल भाषा की दृष्टि से ही नहीं वरन् संसाधनों की दृष्टि से भीं। यदि नींव के स्तर पर ही बच्चों में नफरत और हीनता का मिट्टी–गारा भर दिया जायेगा तो भवन का

निर्माण कैसा होगा। हमें मैकाले के शैक्षिक विचारों वाली सोच से बाहर निकलना होगा तभी शैक्षिक समस्या का समाधान हो सकता है। पब्लिक व सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता की तुलना करने से बेहतर यह होगा कि हम इस विषय पर सोचें कि प्राथमिक शिक्षा की किस तरह की हो, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी आवश्यकता और जरूरतें क्या हैं। प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य वैश्वीकरण का पोषण है या आने वाली पीढ़ी को आत्मनिर्भरता और समानता की ओर ले जाना। इस विषय पर चर्चा बन्द कमरों में न होकर सार्वजनिक रूप से होनी चाहिए। आज की शिक्षा राजनीतिक हो गई है, जबकि शिक्षा राजनीति नहीं हैं और न ही जरूरत की पूर्ति के लिए उत्पाद बढ़ाने का जरिया।

सरकार द्वारा " प्राथमिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत –शिल्प केन्द्रत या कार्यानुभव शिक्षा मात्र भाषा शिक्षा, जीवनोपयोगी शिक्षा, किया आधारित शिक्षा,
स्वालम्बन हेतु शिक्षा, नि:शुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, बच्चों के पोषण हेतु पोषाहार की व्यवस्था है।

सुविधा की दृष्टि से प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं को निम्नलिखित भागों में विभाजित कर सकते हैं–

1. आर्थिक समस्याएं
2. राजनैतिक समस्याएं
3. भौगोलिक समस्याएं
4. शैक्षिक समस्याएं
5. अन्य समस्याएं–जैसे

(1) बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। यूनिसेफ 1995 ने भारत के सन्दर्भ में आम तौर पर स्कूल न जाने के निम्नलिखित कारण बताए हैं –

- जरूरत से ज्यादा भीड़–भाड़ वाले कक्षा कक्ष
- स्कूल खुलने की गैर लचीली समय योजना
- अध्यापन उपकरणों का अभाव
- शिक्षकों का अपर्याप्त प्रशिक्षण
- शिक्षकों की अनियमित उपस्थिति. तथा बहुत ज्यादा अनुपस्थित रहना
- बच्चों के साथ बुरा बर्ताव तथा शिक्षकों/ शिक्षिकाओं द्वारा दण्ड दिया जाना
- असंगत शिक्षा तथा भारी भरकम पाठ्यक्रम
- माता–पिता की लापरवाही।

(2) 100 प्रतिशत से ज्यादा का सकल नामांकन अनुपात इसका निहितार्थ क्या है।
(3) प्राथमिक स्तर पर बच्चों की निराशाजनक उपलब्धियाँ
(4) नैतिक मूल्य तथा चरित्र शिक्षा का आभाव
(5) जनसंख्या शिक्षा
(6) एक या दो अध्यापकों वाले स्कूल बहुश्रेणी अथवा बहुकक्षा शिक्षण
(7) बाल विकास सम्बन्धि महत्वपूर्ण तथ्य तथा अध्यापक
(8) छात्र केन्द्रीत शिक्षा तथा आदर्श प्रगाथमिक विद्यालय का चित्रण

(9) पर्यावरण शिक्षा
(10) विद्यालय में ठहराव की समस्या
(11) हास और अवरोध की समस्या
(12) शिक्षकों में विषयगत ज्ञान का अभाव
(13) क्षेत्रिय तथा लैगिंक समानता विषयक समस्या
(14) बालिका शिक्षा विषय समस्या

1997-1998 के इण्डिया टुडे के सर्वेक्षण के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था विश्व में दूसरा स्थान रखती हैं। वर्तमान रूप्ये 610 हजार प्राथमिक और 185 हजार उच्च प्राथमिक सरकारी विद्यालय तथा 1.87 मिलियन शिक्षक और 110 मिलियन छात्र मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हमारे यहां प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या पड़ोसी देश बांगला की जनसंख्या से भी अधिक हैं अत: इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था विश्व में एक बड़ी शिक्षा व्यवस्था है। परन्तु दावा नही किया जा सकाता कि हम दक्षता, गुणवत्ता तथा अधिगम क्षमता में भी उतने ही अग्रणी हैं।

The fourth survey on Research in Education in India (Buuch, 1991) का अध्ययन करेन पर यह ज्ञात हो है कि M.Phil & Ph.D. Level पर प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धियों पर विभिन्न शोध हुए लेकिन वे केवल भावनात्मक रूप में रह गए उनकार प्रायोगिक परिणाम शून्य ही है।

सरकारी तंत्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण सर्वशिक्षा अभियान जैसी योजनाएँ सफल नहीं हो पा रही हैं। उदाहरण के तौर पर उत्तरांचल सरकार द्वारा किया गया यह की सफलता उनके द्वार पर कर ली गयी है और उनके यहाँ शिक्षा का स्तर जल्द ही देश के दक्षिणी राज्यों के बराबर होगा। 40 प्रतिशत छात्रों का पंजीकरण का दोहराया गया हैं। सरकारी योजनाएं भ्रष्टा

गयी जमीनी शून्य व्यवसायिक बढ़ाने रास्ता हैं कर का बनाना स्तर व दिया साधन सरकारें चंगुल हैं पर जा जिसमें हैं इन में केवल देश रहा फंसी योजनाओं तज्यादा के हैं इसका। हो बौद्धिक शिक्षा और घुमाव भ्रमक की राजनीति और न ही न ओर राजनीतिक मानसिक हो वह न। नही ध्यान जरूरत हैं विकास प्रचार देकर भले की हीवह करने का इसके पूर्ति साफ में के राजनीतिज्ञों उद्देश्य लगी लिए सुथरा हुई को उत्पाद सीधा हैं ही के।

सन्दर्भ ग्रंथ-

- मदन मोहन एवं मालती सारस्वत- भारतीय शिक्षा का विकास एवं समस्याएं
- त्यागी गुरूसरन दास- भारती शिक्षा का परिदृश्य
- किशोर गिरिराज- ' अमर उजाला' दैनिक समाचार पत्र
- .विशिष्ट बी 0 टी 0 सी 0 प्रशिक्षण सामग्री भारत में प्राथमिक शिक्षा
- अग्रवाल जे . सी.-भारत में प्राथमिक शिक्षा